विषय:- ग्राम नांगलवाड़ी जिला बड़वानी में माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में किसान कल्याण वर्ष के तहत हुई प्रथम कृषि कैबिनेट की बैठक ।

2. नांगलवाड़ी में किसानों के हित में रुपये 27,500 करोड़ स्वीकृति, विभिन्न योजनाओं में यह राशि अगले 5 वर्ष हेतु प्रावधानित।

3. नर्मदा नियत्रंण मण्डल की नांगलवाड़ी में सम्पन्न बैठक में बड़वानी जिले में 2 उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना को मिली स्वीकृति ।

किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत मध्यप्रदेश में ग्राम नांगलवाड़ी जिला बड़वानी में देश की पहली कृषि कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में, दिनांक 02.03.2026 को आयोजित की गई । इस कृषि कैबिनेट में, कृषि क्षेत्र से संबंधित (कृषि+पशुपालन+मत्स्य+उद्यानिकी+सहकारिता) कुल राशि 25,678.03 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई । इसके साथ-साथ नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं में कुल राशि 2067.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई । इस प्रकार आज हुई कृषि कैबिनेट बैठक में कुल रुपये 27,746 करोड़ की स्वीकृति कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में दी गई ।

1. पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास- ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अगले 5 वर्षों

तक रुपये 610.51 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई । यह कार्य वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर जारी रहेंगे ।

2. मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्यद्योग नीति, 2026-

आज हुई इस कृषि कैबिनेट में इस नवीन नीति को आज स्वीकृत किया गया तथा इसके तहत अगले 3 वर्षों तक रुपये 3000 करोड़ का निवेश एवं लगभग 20 हजार रोजगार (10 हजार प्रत्यक्ष एवं 10 हजार अप्रत्यक्ष) सृजित होंगे। इस नीति में रुपये 18.50 करोड़ के बजट प्रावधान की स्वीकृति दी गई तथा इसके तहत केज कल्चर को आधुनिक स्वरुप में बढ़ावा देते हुये लगभग 01.00 लाख केज स्थापित किये जायेंगे । इस नीति के तहत मछली पालन संबंधी गतिविधि के साथ ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी को शामिल करते हुये बहुउद्देशीय आजीविका मॉडल के रुप में कार्य होगा ।

3. मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना -

इस योजना के तहत मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, ब्याज अनुदान एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं । इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष एवं अगले वित्तीय वर्ष हेतु रुपये 200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई ।

4. राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन-

इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक योजना लगातार चालू रखने की तथा रुपये 1150 करोड़ की स्वीकृति आज प्रदान की गई । इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में दक्षता की वृद्धि विभिन्न कृषि घटकों का प्रभाव बढ़ाना, दोहराव से बचना आदि संबंधी कार्य किये जायेंगे ।

5. सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना -

इस योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणीय उद्योगों के उन्नयन तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर अगले 5 वर्षों तक, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता निरंतर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । इस हेतु रुपये 1375 करोड़ की स्वीकृति कृषि कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई ।

6. उद्यानिकी के क्षेत्र में पौधशाला उद्यान के तहत रोपणियों में पौध तैयार करना तथा उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज, रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा । अगले 5 वर्षों तक अर्थात वर्ष 2031 तक के लिए रुपये 1738.94 करोड़ की सहायता उद्यानिकी क्षेत्र में कार्यरत कृषकों के पक्ष में की जावेगी ।

7. किसान कल्याण एवं कृषि विकास हेतु रुपये 500 करोड़ से कम वित्तीय आकार की 20 परियोजनाओं को आगामी 5 वर्षों तक अर्थात

31 मार्च, 2031 के लिए निरंतर जारी रखने का निर्णय भी आज लिया गया । इन 20 योजनाओं में अगले 5 वर्षों तक कुल 3502.481 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी कृषि कैबिनेट द्वारा आज प्रदान की गई ।

8. लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम को ऋण प्रदाय करना - सहकारिता विभाग द्वारा जिला बैंकों के माध्यम से, कालातीत ऋणों की पूर्ति किये जाने हेतु कृषकों को फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है । आज हुई इस कृषि कैबिनेट में, सहकारिता विभाग की इस योजना " सहकारी बैंकों के अंशपूंजी सहायता" को अगले 5 वर्षों तक अर्थात 31 मार्च, 2031 तक, रुपये 1975 करोड़ की स्वीकृति के साथ-साथ उक्त सुविधायें कृषकों को निरंतर दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

9. कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना- सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण राशि रुपये 3 लाख तक शून्य प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जाता है । किसानों को प्राप्त हो रही यह महत्वपूर्ण सुविधा एवं सहायता 31 मार्च, 2031 तक निरंतर प्राप्त होती रहे, इसकी स्वीकृति एवं रुपये 3909 करोड़ की स्वीकृति आज कृषि कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई ।

10. सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं को आवश्यक सहयोग जैसे अंशपूंजी, ऋण तथा अनुदान आदि सुलभ कराने एवं विभागीय गतिविधियों सुचारु संचालन हेतु 12 प्रचलित योजनाओं के भी 31 मार्च, 2031 तक निरंतर प्रचलित रहने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन 12 योजनाओं हेतु अगले 5 वर्षों की अवधि हेतु रुपये 1073 करोड़ की स्वीकृति भी कृषि कैबिनेट द्वारा दी गई।

11. कृषि क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अधीन चल रहीं विभिन्न योजनाओं के सुचारु संचालन एवं मानीटरिंग हेतु विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत रुपये 1229 करोड़ अगले 5 वर्षों हेतु स्वीकृत किये गये ।

12. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत सोर्टेड सेक्स्ड सीमन उत्पादन परियोजना -

इस योजना के तहत चिन्हित नस्ल के मादा गौ-भैंस वंशीय पशुधन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पशु पालकों को आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जाता है । इस योजना से पशु पालकों को निरंतर लाभ प्राप्त होता रहे, इस हेतु रुपये 656.00 करोड़ तथा इस योजना को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित करने की स्वीकृति आज प्रदान की गई।

13. पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण -

इस योजना के तहत पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ दिया जाता है ऐसी 14 योजनाओं के तहत अगले 5 वर्षों हेतु (31 मार्च, 2031 तक) रुपये 1723.00 करोड़ राशि की आज हुई इस कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई ।

14. पशुपालन एवं डेयरी में प्रचलित 11 योजनाएं -

पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में पशु प्रजनन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी प्रक्षेत्र, रोग उन्मूलन,पशुओं का टीकाकरण, गहन पशु विकास परियोजना आदि पर अगले 5 वर्षों तक निरंतर कार्य चलेंगे । इससे इस क्षेत्र के पशुपालकों को लाभ प्राप्त होगा । इन सम्पूर्ण कार्यों में कृषि कैबिनेट द्वारा रुपये 6518.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई ।

उपरोक्तानुसार आज हुई इस कृषि कैबिनेट में कृषि संबंधित क्षेत्रों (कृषि+उद्यानिकी+मत्स्य+पशुपालन+सहकारिता) में कुल 25,686 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई ।

उक्त के अतिरिक्त नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले में तहसील वरला के 33 ग्रामों में तथा तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों में अल्प वर्षा क्षेत्र तथा भूजल स्तर, अत्यधित कम होने के कारण 2 सिंचाई परियोजनाओं कुल राशि

रुपये 2067.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति भी कृषि कैबिनेट द्वारा आज प्रदान की गई है ।

यह परियोजनायें निम्नानुसार हैं :-

1. वरला, उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना-

इस योजना के तहत नर्मदा नदी से 51.42 एम.सी.एम. जल उद्वहन करते हुए इस तहसील के 33 गावों की 15500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी । इस परियोजना की लागत रुपये 860.53 करोड़ रुपये है ।

2. पानसेमल उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना-

इस योजना के तहत तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों की 22500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी । इसके तहत नर्मदा नदी से 74.65 एम.सी.एम. जल उद्वहन किया जायेगा । इस परियोजना की लागत रुपये 1207.44 करोड़ है ।

अत: आज ही इस कृषि केबिनेट में कृषि, पशुपालन, मत्सय, उद्यानिकी, सहकारिता एवं नर्मदा नियत्रंण मण्डल बैठक में माइक्रो सिंचाई परियोजना में कुल 27,746.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षो में व्यय की जावेगी। किसान कल्याण वर्ष की यह पहली केबिनेट है भविष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कृषि केबिनेट का आयोजन कर किसान कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए जाएगें।